वॉल्यूम 2 अंक 2 सितम्बर 2019

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

संदेश

अरुण कुमार सिन्हा

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

भारत और भूटान ने जल क्षेत्र में लंबी अवधि के सहयोग से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है. भारत और भूटान के माननीय प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 720 मेगावाट के मान्देछु जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया. यह परियोजना दर्शाती है कि कैसे दोनों राष्ट्र एक साथ काम करते हुए लोगों के जीवन में समृद्धि एवं विकास ला सकते हैं.

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जल शक्ति अभियान जल संबंधी मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने में सक्षम रहा है और अब इस पर व्यापक रूप से चर्चा और बहस हो रही है. जल सुरक्षा की बढ़ोतरी के लिए एक देशव्यापी प्रयास में, विशेष रूप से जल की कमी वाले जिलों में, जल शक्ति अभियान (जेएसए) ने अब तक 256 जिलों में 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण उपाय प्रदत्त किए हैं. इन उपायों के तहत लगभग 4.25 करोड़ पौधे लगाए गए. अनुमान है कि इस अभियान में 2.64 करोड़ लोगों ने भाग लिया है व इसे जनांदोलन का रूप दिया है. केंद्रीय जल आयोग के 140 से अधिक अधिकारी इस अभियान के लिए अपना तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं.

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है कि आने वाले दिनों में, केंद्र और राज्य मिलकर जल-जीवन मिशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि सभी को पाइप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो और इस के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निश्चित की गई है.

देश को अगस्त के महीने में बहुत गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा. के.ज.आ. सूचना (डेटा) संग्रह नेटवर्क ने दर्शाया है कि 25 स्थानों पर नदियाँ पूर्व में दर्ज किए गए उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) से ऊपर बही हैं. इस बाढ़ ने देश भर में विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में जीवन और संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया है. इस जलप्रलय का मुख्य कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ थी. मानसून के मौसम के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से 12 राज्यों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 11 अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया गया है. दूसरी ओर, इन घटनाओं ने जुलाई के अंत में 9% की मानसून की कमी को दूर कर दिया और अगस्त के अंत में औसत बारिश सामान्य से अधिक हो गई. इस एक महीने की अवधि में के.ज.आ. द्वारा निगरानी किए जा रहे प्रमुख जलाशयों का सक्रिय (लाइव) संग्रहण 33% से बढ़कर 76% हो गया. कई राज्य नवीन समाधानों पर काम कर रहे हैं जैसे कि जलाशयों पर तैरने वाली सौर पैनलों के उपयोग से बिजली पैदा करने के साथ-साथ वाष्पीकरण के नुकसान को कम किया जा सके. उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहंद जलाशय के लिए ऐसी ही एक योजना को स्वीकृति दी है.

नीति आयोग ने माननीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिती में दिनांक 23.08.2019 को समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) 2.0 जारी किया. सीडब्लूएमआई अपने जल प्रबंधन प्रयासों के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए एक रूपरेखा और आने वाले दिनों में सुधार के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है. गुजरात सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा. इस रिपोर्ट को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है.

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-08/CWMI-2.0-latest.pdf

भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों द्वारा भूटान में 720 मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन

माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा सीडब्ल्यूईएस समूह 'क' अधिकारियों हेतु 31वें प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ

आगामी कार्यक्रम

6th INDIA WATER WEEK 2019

Water Cooperation-Coping With 21st Century Challenges

24-28 सितंबर 2019 विज्ञान भवन, नई दिल्ली

विषय सूची

- जल शक्ति अभियान
- प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- देश में बाढ़ की स्थिति
- घग्गर स्थायी समिति
- आईएमसीटी दौरा
- बीआईएस अनुभागीय समिति
- सरदार सरोवर बांध का दौरा
- सिकसर बांध के मुद्दे
- सीडब्ल्यूसी-सीपीआर संवाद मंच
- सीडब्ल्यूआरसी की बैठक
- सिंचाई एटलस
- डीआरआईपी के तहत गतिविधियाँ
- जलाशयों में जल संरक्षण
- ग्लेशियल लेक की निगरानी
- स्वतंत्रता दिवस समारोह
- दीर्घा (गेलरी)
- उद्योगों का दौरा
- समाचार में जल क्षेत्र
- राज्य से खबरें
- अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण
- इतिहास से - कोसी परियोजना

जल शक्ति अभियान

जल सुरक्षा की बढ़ोतरी के लिए एक देशव्यापी प्रयास में, विशेष रूप से जल की कमी वाले जिलों में, केंद्र द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान (जेएसए) ने अब तक 256 जिलों में 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण उपाय प्रदत्त किए हैं. इनमें से 1.54 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन उपाय हैं, 20000 पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प से संबंधित हैं, 65000 से अधिक पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं हैं और 1.23 लाख जल विभाजक (वाटरशेड) विकास परियोजनाएं हैं. इस अभियान में अनुमान है कि 2.64 करोड़ लोग पहले ही भाग ले चुके हैं और इसे जन आंदोलन का रूप दिया है. इन उपायों के तहत लगभग 4.25 करोड़ पौधे लगाए गए थे. जल शक्ति अभियान के पहले चरण के परिणाम की समीक्षा नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव द्वारा की गई. केंद्रीय जल आयोग के 140 से अधिक अधिकारी इस गतिविधि के लिए अपना तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं.

जेएसए के तहत विभिन्न जिलों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली भी विकसित की गई है. 30.08.2019 तक कार्यक्रम के लिए 3 शीर्ष जिले और उनके संबंधित तकनीकी अधिकारी निम्नानुसार हैं.

राष्ट्रीय रैंक	जिले का नाम	राज्य का नाम	कुल स्कोर	तकनीकी अधिकारी/सहयोग
1	कासगंज	उत्तर प्रदेश	87.41	सीएसएमआरएस
2	बनासकांठा	गुजरात	83.31	रूपेश डी, उप निदे.एवं अभिषेक गुप्ता, उप निदे., के.ज.आ.
3	महबूब नगर (14)	तेलंगाना	82.13	कौशल कुमार, उप निदे., के.ज.आ.

प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा 'समूह क' अधिकारियों (संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नव नियुक्त सहायक निदेशकों/सहायक अधिशासी अभियंताओं) के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम हर साल आयोजित होने वाले एनडब्ल्यूए के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है.

31वीं आईटीपी 20.08.2019 से शुरू किया गया है और यह 07.02.2020 को समाप्त होगा. भर्ती किए गए चौवालिस (44) नए सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियंता इस 24 सप्ताह के आईटीपी में भाग ले रहे हैं. आईटीपी का उद्घाटन 20.08.2019 को एनडब्ल्यूए, पुणे में माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया था. श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव (डीओडब्लूआर, आरडी एंड जीआर) और श्री अरुण कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई.

इस अवसर पर, माननीय मंत्री ने जल प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ युवा अधिकारियों के बीच नवीन सोच को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि जल संसाधन की उपलब्धता में प्रतिस्पर्धात्मक मांग, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण और अधिक दोहन के कारण कमी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि जल संरक्षण को एक क्रांति के रूप में लिया जाना चाहिए और कहा कि इस क्षेत्र में जल शक्ति अभियान (जेएसए) जैसी पहल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि अगले पांच वर्षों में भारत को पाँच ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की चुनौतियों को प्राप्त करने के लिए जल संसाधन के विकास और प्रबंधन के प्रयासों के साथ-साथ सभी के द्वारा किए जाने वाले जल संरक्षण के प्रयासों को एक साथ करके जल अवसंरचना को मजबूत करना बहुत जरूरी है. उन्होंने उल्लेख किया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा 'समूह क' के अधिकारी एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं.

भारत - बांग्लादेश सहयोग

भारत और बांग्लादेश के बीच सचिव स्तर की एक बैठक 08.08.2019 को आयोजित हुई थी. भारतीय दल का नेतृत्व श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, सचिव, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा किया गया और इसमें श्री जे.सी. अय्यर, आयुक्त (बाढ़ प्रबंधन), ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि. तथा श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग व अन्य शामिल थे.

भारत और बांग्लादेश ने गंगा के पानी की इष्टतम उपयोगिता हेतु जैसा कि गंगा जल साझेदारी संधि 1996 के अंतर्गत बांग्लादेश द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति की स्थापना हेतु सहमति की है. यह सहमति भी हुई है कि सात नदियों नामत: फेनी, गुमटी, मनु, खोवई, मुहुरी, तोरसा व जलढाका के लिए अंतिरम जल—साझेदारी समझौता हेतु एक कार्यढांचा भी बनाया जाए. दोनों देशों ने ट्रांसबाउँडरी नदियों के प्रदुषण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की. इससे भारत और बांग्लादेश के बीच जल संसाधन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि होगी.

बाढ़ पूर्वानुमान पर नेपाल के साथ बैठक

भारत और नेपाल के लिए नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क को अंतिम रूप देने के लिए भारत और नेपाल प्रत्येक से तीन सदस्यों की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था. संयुक्त टीम ने अपनी पहली बैठक 22.08.2019 को पटना में आयोजित की जिसमें निम्नलिखित निर्णय किए गए.

- नेपाल में 281 स्टेशनों का एक नेटवर्क भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिसका डेटा फ्लड फोरकास्ट मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाएगा.
- इन स्टेशनों का रियल टाइम हाइड्रो-मौसम संबंधी डेटा भारत के साथ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एफटीपी) के माध्यम से साझा किया जाएगा.

इससे भारत को बेहतर बाढ़ प्रबंधन तथा बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बाढ़ के दौरान निवारक उपाय करने में लाभ होगा. दोनों देशों के अधिकारियों ने केन्द्रीय जल आयोग के हाजीपुर एवं गांधीघाट प्रेक्षण स्थलों का दौरा किया.

देश में बाढ़ की स्थिति

अगस्त के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा के कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा.

कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में के.ज.आ. के 25 स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई. कुछ स्टेशनों पर दो दिनों से अधिक समय तक ऐसी स्थिति बनी रही. महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के तेरवाड़ में पंचगंगा नदी में 7 से 14 अगस्त, 2019 तक बहाव एचएफएल से ऊपर था.

अगस्त, 2019 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, एनसीटी दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 70 के.ज.आ. स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई.

असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के राज्यों में के.ज.आ. के 41 स्टेशनों पर अगस्त, 2019 तक सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गई.

अगस्त, 2019 तक 61 जलाशयों और बांधों के लिए इनफ्लो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं.

घग्गर स्थायी समिति

घग्गर स्थायी समिति (जीएससी) की 29वीं बैठक 29.08.19 को के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली में सदस्य(आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- आबादी वाले क्षेत्रों को बचाने के लिए रिंग बंड द्वारा त्वरित बाढ़ प्रबंधन उपाय.
- डेटा संग्रह कार्य के लिए सहमत निविदा का स्कोप सीडबल्यूपीआरएस, पुणे के साथ उनके विचारों के लिए साझा किया जाना चाहिए
- पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के अधिकारी संयुक्त रूप से स्वीकृत निविदा नियमों और शर्तों के अनुसार डेटा संग्रह के लिए भुगतान का तरीका तय करेंगे और डेटा संग्रह का कार्य 10 दिनों के भीतर अवार्ड किया जाएगा.
- डेटा संग्रह के लिए काम 01.10.2019 (मानसून के मौसम के बाद) से शुरू किया जाना चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

घग्गर बेसिन में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, और जल निकासी कार्यों की जांच और समन्वय करने के लिए और अंतरराज्यीय पहलू से बेसिन में व्यक्तिगत योजनाओं के लिए उनके कार्यान्वयन और समझौते को मंजूरी के लिए प्राथमिकता देने के लिए जीएससी का गठन फरवरी 1990 में किया गया था. राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों का प्रतिनिधित्व जीएससी में किया जाता है.

बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का विस्तार

के.ज.आ. ने अपने एफएफ नेटवर्क का विस्तार 325 स्टेशनों तक कर लिया है, जिसमें से 198 एफएफ स्टेशन लेवल जबकि 127 इनफ्लो एफएफ स्टेशन हैं. वर्ष 2019 के दौरान इस नेटवर्क के तहत कुल 76 अतिरिक्त स्टेशन शामिल किए गए हैं जिन्हे वर्ष 2020 तक पूरा किया जाना था.

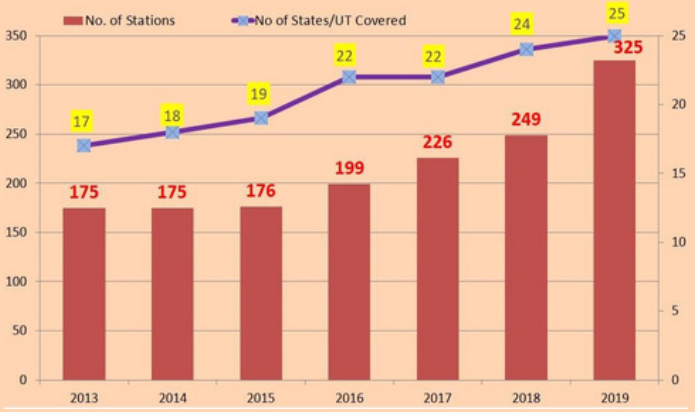

राज्य	लेवल पूर्वानुमान स्टेशन	इनफ्लो पूर्वानुमान स्टेशन	योग
आंध्र प्रदेश	10	9	19
अरुणाचल प्रदेश	03	0	03
असम	30	0	30
बिहार	40	3	43
छत्तीसगढ़	01	2	03
गुजरात	06	7	13
हरियाणा	01	1	02
हिमाचल प्रदेश	01	0	01
जम्मू और कश्मीर	03	0	03
झारखंड	02	15	17
कर्नाटक	01	14	15
केरल	03	2	05
मध्य प्रदेश	02	9	11
महाराष्ट्र	08	15	23
ओडिशा	12	7	19
राजस्थान	02	11	13
सिक्किम	03	5	08
तमिलनाडु	04	11	15
तेलंगाना	05	7	12
त्रिपुरा	02	0	02
उत्तर प्रदेश	39	4	43
उत्तराखंड	04	2	06
पश्चिम बंगाल	12	4	16
एनसीटी दिल्ली	02	0	02
दमन और दीव	01	0	01
कुल	197	128	325

बाढ़ / भूस्खलन के मद्देनजर घटनास्थल पर मूल्यांकन के लिए अंतर-मंत्रालयी टीम

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 19.08.2019 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने हाल में आई बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का गठन किया है.

अब तक आईएमसीटी संबंधित प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद केवल एक बार प्रभावित राज्यों का दौरा करते थे. अब उन्हें पहले दौर की यात्रा के लिए पहले से ही गठित किया गया है. नुकसान और राहत कार्यों के विस्तृत आकलन के लिए ज्ञापन सौंपने के बाद वही आईएमसीटी अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के लिए अंतिम सिफारिशें करने के लिए फिर से राज्य का दौरा करेगी. मानसून 2019 के दौरान बाढ़ / भूस्खलन की ऑन-द-स्पॉट स्थिति के आकलन के लिए के.ज.आ. के अधिकारियों को विभिन्न अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों में नामित किया गया है। अगस्त 2019 में इन अधिकारियों ने टीम के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और बिहार का दौरा किया है।

कर्नाटक

कर्नाटक में आईएमसीटी ने 24.08.2019 से 27.08.2019 के दौरान कर्नाटक के बेलगावी, बागलकोट, गडग, धारवाड़ और कोडागु जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. श्री जितेंद्र पवार, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., बेंगलुरु ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) में जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया.

उत्तराखंड

श्री सुधीर कुमार (जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले) के साथ अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम 29.08.2019 की शाम को मोरी तहसील (उत्तरकाशी जिला) के अराकोट क्षेत्र और 30.08.2019 को घाट तहसील (चमोली जिला) पहुंची. टीम द्वारा 2019 के मानसून के दौरान होने वाले भूस्खलन, भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और अचानक आई बाढ़ के कारण नुकसान के आकलन के लिए घटनास्थल पर जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत की.

बिहार

बिहार सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ज्ञापन सौंपकर जुलाई, 2019 के दौरान बाढ़ के कारण जान-माल के नुकसान के मद्देनजर 2700.30 करोड़ रूपए की सहायता मांगी है. इसके बाद, केंद्र सरकार ने श्री रमेश कुमार गन्ता, संयुक्त सचिव, एनडीएमए के नेतृत्व में 7 सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय समिति का गठन किया. श्री मुकेश कुमार सिंह, निदेशक, निचली गंगा बेसिन संगठन, के.ज.आ., पटना ने आईएमसीटी में जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया. आईएमसीटी ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 28.08.2019 से सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिलों का दौरा किया.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में बाढ़ के मद्देनजर घटनास्थल पर स्थिति के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय दल (आईएमसीटी) ने अगस्त माह के अंत में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. श्री मिलिंद पनपाटिल, निदेशक, के.ज.आ., नागपुर ने आईएमसीटी में जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया.

राज्य	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान सर्व श्री	टिप्पणी
पंजाब	विनीत गुप्ता, अधीक्षण अभियंता (समन्वय), सिंधु बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, चंडीगढ़	बाढ़
बिहार	मुकेश कुमार सिंह, निदेशक, प्रबोधन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, पटना	बाढ़
त्रिपुरा और मेघालय	अभिषेक सिन्हा , अधीक्षण अभियंता, मेघना सर्किल , केंद्रीय जल आयोग, सिलचर	बाढ़ / भूस्खलन
राजस्थान	एस.डी. शर्मा, निदेशक, प्रबोधन और मूल्यांकन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, जयपुर	बाढ़
गुजरात	डी.एस. चासकर, अधीक्षण अभियंता, हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन सर्कल, केंद्रीय जल आयोग, गांधीनगर	बाढ़
उत्तराखंड	सुधीर कुमार, अधीक्षण अभियंता, हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन सर्कल, केंद्रीय जल आयोग, देहरादून	बाढ़ / भूस्खलन
हिमाचल प्रदेश	ओ.पी. गुप्ता, निदेशक, प्रबोधन और मूल्यांकन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, शिमला	बाढ़ / भूस्खलन
असम	वी.डी. रॉय, अधीक्षण अभियंता, हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन सर्कल, केंद्रीय जल आयोग, गुवाहाटी	बाढ़ / भूस्खलन
केरल	वी. मोहन मुरली, अधीक्षण अभियंता, कावेरी एंड साउथर्न रिवर सर्कल, केंद्रीय जल आयोग, बेंगलुरु	बाढ़ / भूस्खलन
कर्नाटक	जितेंद्र पवार, अधीक्षण अभियंता (एच ओ एंड सी.सी.), प्रबोधन संगठन (दक्षिण), केंद्रीय जल आयोग, बेंगलुरु	बाढ़ / भूस्खलन
महाराष्ट्र	मिलिंद पनपाटिल , निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर	बाढ़

27.08.2019 को बेंगलुरू में कर्नाटक सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ डी-ब्रीफिंग बैठक

जुनिपेट, कर्नाटक में मलाप्रभा नदी पर स्थित बहा हुआ केबल ब्रिज

26.08.2019 को कर्नाटक के मुधोल के पास बाढ़ के कारण खराब हुई गन्ने की फसल

बीआईएस - अनुभागीय समिति की बैठक (डब्ल्यूआरडी -15)

श्री एस.के. सिबल, मुख्य अभियंता, डिजाइन(एनएंडडब्ल्यू), के.ज.आ. ने 29.08.2019 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में "हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस स्ट्रक्चर्स सेक्शनल कमेटी" डब्ल्यूआरडी 15 की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक में, आईएस 9120: "अंडरग्राउंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में कैविटीज के नियोजन, लेआउट और डिजाइन के लिए दिशानिर्देश" और आईएस 4720: "कोड ऑफ़ प्रैक्टिस फॉर वेंटिलेशन ऑफ़ सरफेस हाइडल पावर स्टेशन" उनके संशोधन पर अन्य एजेंडों के साथ विस्तार से चर्चा की गई.

सरदार सरोवर बांध का दौरा

श्री एस.के. सिबल, मुख्य अभियंता, डिजाइन(एनएंडडब्ल्यू), श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता, डीएसओ और श्री अनिल जैन, निदेशक, सीएमडीडी(एनएंडडब्ल्यू) ने के.ज.आ., सीएसएमआरएस, सीडब्ल्यूपीआरएस के अधिकारियों से मिल कर बने बहु-विषयक समिति के एक हिस्से के रूप में 20 से 22 अगस्त, 2019 तक सरदार सरोवर बांध के जलाशय को तेजी से भरने से बांध की सुरक्षा पर प्रभाव का आकलन करने के लिए निरीक्षण किया.

सिकसर बांध, छत्तीसगढ़ के रॉक स्पिल चैनल का बढ़ता हुआ अपरदन

सिकसर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले के सिकसर गाँव के पास महानदी नदी बेसिन की एक बड़ी सहायक नदी, पैरी नदी पर बना है. परियोजना में एक मृदा बांध (31.7 मीटर ऊँचा और 876.31 मीटर लंबा), और सेडल मृदा बांध (9.32 मीटर ऊँचा और 664.0 मीटर लंबा) जिसमे साइड चैनल स्पिलवे 243.23 मीटर लंबा, 9.14 मीटर x 3.96 मीटर आकार के ऊर्ध्वाधर लिफ्ट गेट्स (22 नग) के साथ दाहिने किनारे पर है. परियोजना अधिकारियों ने बताया कि 1977 में वेस्ट वियर के संचालन के पहले वर्ष के दौरान, जब स्पिल चैनल के माध्यम से लगभग 1395 क्यूमेक्स बाढ़ निस्सरण हुआ, चैनल बेड का अपरदन और कटाव 1.5 मीटर से 11 मीटर तक कटाव गहराई के साथ देखा गया. साल-दर-साल बाढ़ के स्पिल चैनल से गुजरने के साथ अपरदन उसी अनुसार बढ़ता जा रहा है.

प्रॉजेक्ट अथॉरिटी के अनुरोध पर, श्री एम. लाल, मुख्य अभियंता, डिजाइन(एनडब्ल्यूएंडएस), श्री कयूम मोहम्मद, निदेशक, सीएमडीडी(एनडब्ल्यूएंडएस) और श्री मुकेश कुमार, उप निदेशक, सीएमडीडी, के.ज.आ. ने 28.08.2019 को समस्या का आकलन करने के लिए सिकसर बांध स्थल का दौरा किया.

के.ज.आ.-सीपीआर संवाद मंच

श्री ऋषि श्रीवास्तव, निदेशक, केंद्रीय जल आयोग ने 26.08.2019 को सीपीआर में टीआरईएडीएस (ट्रांसबाउंडरी रिवर्स, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज) कार्यक्रम की वार्ता-श्रंखला में "जल संसाधन आकलन, भारत के जल संकट को समझना: भारत का जल संसाधन पोटेन्शियल" विषय पर एक विस्तृत वार्ता की. के.ज.आ.-सीपीआर डायलॉग फोरम सीपीआर और केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार का एक सहयोगी प्रयास है. यह वार्ता जल नीति के उपकरणों और शासन की रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए योगदान करते समय जल संकट के विचार और एक ठोस बातचीत को गंभीरता से सम्मिलित करने के उद्देश्य से थी.

श्री ऋषि श्रीवास्तव ने के.ज.आ. और इसरो (2019) द्वारा स्पेस इनपुट का उपयोग करके भारत में पानी की उपलब्धता के पुन: अध्ययन के बारे में विस्तार से बताया जो भारत में पानी की उपलब्धता का अब तक का सबसे व्यापक और विश्वसनीय अनुमान है. के.ज.आ. द्वारा पूर्व में भी प्रयास किए गए थे. अंतिम मूल्यांकन 1993 में हुआ था, जब कुल जल संसाधनों का आकलन 1869 बीसीएम था. इस मूल्यांकन की कुछ सीमाएँ जैसे कि इस अवधि के दौरान सभी बेसिनों का अध्ययन नहीं किया गया, भूजल निकालने का अनुमान लगाया गया केवल दो वर्षों के आंकड़ों के आधार पर प्रक्षेपित किया गया, लघु सिंचाई परियोजनाओं से उपयोग ज़्यादातर अनुपलब्ध थे, वृहद् और मध्यम परियोजनाओं से जल उपयोग हमेशा उपलब्ध नहीं था (ज्यादातर अनुमानित), सिंचाई से वापसी का प्रवाह डायवर्सन के 10% के रूप में माना गया, आदि थीं. 2019 का आकलन अंतरिक्ष आदानों पर निर्भर उपरोक्त सीमाओं को खत्म करने का एक प्रयास है. उपयोग और वापसी के प्रवाह का आकलन करने के बजाय, उप-बेसिन स्तर पर संशोधित थार्नथ्वेट माथेर समीकरण का उपयोग करके वाष्पीकरण का अनुमान लगाया गया है. पानी के संतुलन को पिक्सेल स्तर (56 मीटर x 56 मीटर) पर ले जाया गया और फिर देखे गए निस्सरण और बारिश के अंशांकन और सत्यापन के बाद उप-बेसिन स्तरों पर एकत्र किया गया. यह आकलन एनआरएससी से लैंड यूज लैंड कवर (एलयुएलसी) मानचित्र , सीजीडब्ल्यूबी के अन्य डेटा सेट के अलावा, विभिन्न एजेंसियों के डेटा सेट का प्रयोग करके 1999 बीसीएम की उपलब्धता पर पहुंचा. परिणाम बताते हैं कि नदी बेसिन में एक विशाल स्थानिक परिवर्तनशीलता है. फल्केनमार्क वाटर स्ट्रेस / स्कारसिटी सूचकांक के अनुसार अधिकांश नदी घाटियां वाटर स्कार्स या वाटर स्ट्रेस्ड हैं. इस चर्चा में परिवर्तनशीलता पर विचार-विमर्श हुआ व क्षमता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपायों और भविष्य की मांगों को पूरा करने में पर चर्चा हुई.

कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की बैठक

कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की महीने के दौरान तीन बैठकें हुईं. श्री नवीन कुमार, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूआरसी की अध्यक्षता में 01.08.2019, 08.08.2019 और 13.08.2019 को क्रमश: 12वीं बैठक बेंगलुरु में, जबकि 13वीं और 14वीं बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गईं. इन बैठकों के दौरान, कावेरी बेसिन में जल-मौसम संबंधी स्थितियों की समीक्षा की गई. जल वर्ष 2018-19 के लिए मौसमी और वार्षिक जल खाते की मसौदा रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई.

भारत का सिंचाई एटलस

भारत का अंतिम सिंचाई एटलस 1987 में प्रकाशित हुआ था. इसको अपडेट करने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन सदस्य (डब्ल्यूपीएन्डपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में किया गया. आईडीसी की पहली बैठक 23-08-2019 को हुई और इसमें हार्ड और डिजिटल प्रारूप दोनों में अद्यतन एटलस लाने का निर्णय लिया गया.

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आईडीसी के सदस्यों, मुख्य अभियंता, पीएमओ, के.ज.आ.; मुख्य अभियंता, एनडब्ल्यूए, के.ज.आ., पुणे; निदेशक, एनडब्ल्यूआईसी; हेड, डब्ल्यूआरएडी, एनआरएससी और निदेशक, एनएटीएमओ को लेकर एक कार्यदल का गठन किया गया. कार्यदल सितंबर 2019 तक एटलस में शामिल किए जाने वाले विस्तृत प्रकरण/विशेषताओं को अंतिम रूप देगा और विचार और निर्णय के लिए आईडीसी के समक्ष रखेगा. यह भी तय किया गया कि सूक्ष्म सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्र को अलग से दर्शाया जाए और के.ज.आ. द्वारा निश्चित किए गए 20 बेसिन ही प्लेट तैयार करने का आधार होंगे.

डीआरआईपी (ड्रिप) के तहत गतिविधियाँ

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) चरण- II और चरण- III के लिए **स्टेट कंसल्टेशन एंड अप्रेजल की बैठक** सचिव (डब्ल्यूआरडी) और राजस्थान के अन्य अधिकारियों और उत्तर प्रदेश डब्ल्यूआरडी के साथ क्रमशः 19-08-19 और 30-09-19 को आयोजित की गई. बैठकों में सीडब्ल्यूसी और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भी भाग लिया. केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीएमपीयू) और विश्व बैंक की टीम द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं. प्रस्तुति में मोटे तौर पर बजट परिव्यय, स्थानिक कवरेज, समयसीमा, भाग लेने वाली एजेंसियां, वित्त पोषण पैटर्न, कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र और परियोजना के लिए प्रारंभिक गतिविधियों के लिए समय सीमा शामिल थी.

राजस्थान

उत्तर प्रदेश

परियोजना की गतिविधियों की कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा करने और परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए 21 से 22 अगस्त 2019 के दौरान ड्रिप के 14वें **इंप्लेमेंटशन सपोर्ट एंड रिवियू मिशन** ने भुवनेश्वर, ओडिशा का दौरा किया. मिशन के दौरान सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आइए) और सीपीएमयू -के.ज.आ. और विश्व बैंक की टीम ने भाग लिया और आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार-विमर्श के बाद समग्र प्रगति, कार्यान्वयन व्यवस्था, मुख्य चुनौतियों और कार्यान्वयन और संवितरण के लिए भविष्य की रणनीति पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं.

समीक्षा मिशन

टीपीआरएम

मिशन के दौरान, सभी भागीदार राज्यों में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) की स्थापना; इंजीनियरिंग और प्रबंधन सलाहकार (ईएमसी) के लिए टीओआर और आरएफपी तैयार करना और खरीद शुरू करना; बांध सुरक्षा समीक्षा पैनलों (डीएसआरपी) की स्थापना; ड्रिप-II में शामिल करने के लिए बांधों की एक सूची प्रदान करना; और ड्रिप-II गतिविधियों के लिए बजट लाइन बनाने पर चर्चा की गई.

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और वर्ल्ड बैंक द्वारा 22.08.2019 को दिल्ली में **ट्राइपारटाइट पाइपलाइन समीक्षा बैठक (टीपीआरएम)** का आयोजन किया गया था, जिसमें चल रहे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) सहित विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. सीपीएमयू के.ज.आ. के अधिकारी, ने टीपीआरएम में चल रहे ड्रिप और आरंभ किए गए ड्रिप चरण II और चरण III के लिए प्रगति की गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया, जिसमें 20 एजेंसियों के साथ 18 राज्यों में सम्मिलित है. बैठक के दौरान डीआरआईपी चरण II और चरण III की ऋण हेतु बातचीत, हस्ताक्षर और प्रभावशीलता के लिए समय सीमा पर चर्चा की गई.

जलाशयों में जल संरक्षण

केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 100 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरुवार को एक साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है. अगस्त महीने के दौरान 7 अतिरिक्त जलाशयों को इस निगरानी में शामिल किया गया है.

इन 107 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 166.17 बीसीएम है जो कि देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की लाइव स्टोरेज क्षमता का लगभग 64.45% है. जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 29.08.2019 के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 126.631 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का 76% है. 107 जलाशयों में उपलब्ध लाइव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के भंडारण का 111% और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का 125% है.

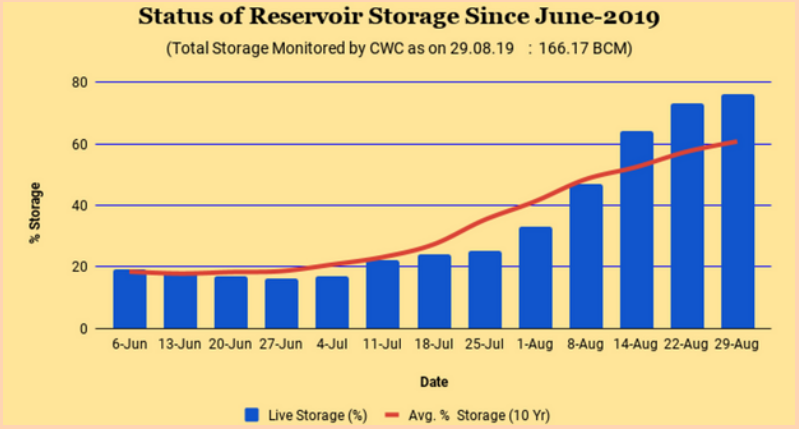

ग्लेशियल लेक की निगरानी

हर साल जून से अक्टूबर के दौरान, के.ज.आ. हिमालयी क्षेत्र में 50 हेक्टेयर से बड़े ग्लेशियल लेक और जल निकायों के आकार पर उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए मॉनिटरिंग करता है. इन्हें वर्ष 2009 में डिजिटल किया गया और वर्ष 2009 में आकार के संबंध में इनके वर्तमान आकारों का विश्लेषण किया गया. क्लाउड-फ्री डेटा की उपलब्धता के कारण निगरानी की संख्या भिन्न-भिन्न है. जून -19 और जुलाई -19 में उनके आकार भिन्नता का सारांश आसन्न चार्ट में दिया गया है.

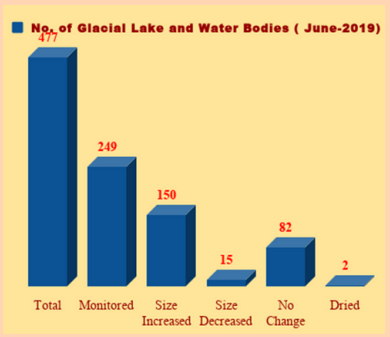

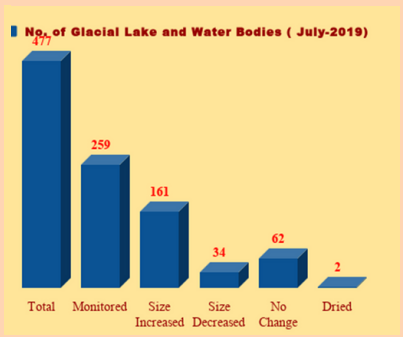

पूर्ण रिपोर्ट निम्न URL से प्राप्त की जा सकती है:

http://cwc.gov.in/sites/default/files/admin/cwc-lakes-monitor-report-june-2019.pdf

स्वतन्त्रता दिवस समारोह

लखनऊ

नई दिल्ली

हैदराबाद

गुवाहाटी

कोयंबटूर

गांधीनगर

पुणे

कोलकाता

भुवनेश्वर

बेंगलुरु

दीर्घा

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने सप्त-कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सन कोसी भंडारण-सह-डायवर्सन योजना (नेपाल) की डीपीआर बनाने और सर्वेक्षण कार्यों के लिए भारत-नेपाल संयुक्त परियोजना कार्यालय को चालू रखने पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए.

अध्यक्ष, के.ज.आ. दिनांक 01.08.2019 को विभिन्न सत्रों, पैनल चर्चाओं आदि जो कि 24-28 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारत जल सप्ताह -2019 के तहत आयोजित होगी, के लिए नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए.

जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की ओर से के.ज.आ. ने 28 से 31 अगस्त 2019 के दौरान कोलकाता में केंद्रीय कलकत्ता विज्ञान और संस्कृति संगठन द्वारा युवाओं के लिए आयोजित २३ वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया. विभिन्न स्कूलों के छात्र / शिक्षक और अन्य लोग स्टाल देखते हुए

दिल्ली में बाढ़ के दौरान यमुना में डिस्चार्ज लेते हुए के.ज.आ. की टीम

राउरकेला में के.ज.आ. द्वारा वेदव्यास घाट पर स्वच्छता अभियान

झारखंड में सिंचाई योजनाओं के लाभों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करते हुए के.ज.आ. अधिकारी

एनडब्ल्यूएम पुरस्कारों हेतु जमीनी सत्यापन के लिए उद्योग का दौरा

श्री विनीत गुप्ता, एसई(सी), आईबीओ, चंडीगढ़ द्वारा 29.08.2019 को एनडब्ल्यूएम पुरस्कारों हेतु मैसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, लुधियाना के प्रार्थना पत्र की जमीनी सत्यापन के लिए एक दौरा किया गया. इसी प्रकार श्री जी.एल. बंसल, निदेशक और श्री मयंक, उप निदेशक, एमएंडए निदेशालय, के.ज.आ. आगरा ने संयुक्त रूप से एलपीजीसीएल द्वारा प्रस्तुत एनडब्ल्यूएम पुरस्कार आवेदन के सत्यापन के संबंध में 21 से 22 अगस्त 2019 के दौरान ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एलपीजीसीएल), जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का दौरा किया.

यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, लुधियाना द्वारा जल संरक्षण के प्रयास

एलपीजीसीएल, ललितपुर द्वारा जल संरक्षण के प्रयास

जल क्षेत्र से समाचार

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण चेन्नई एयरपोर्ट पर करेगा वर्षा जल संचयन (राजस्थान पत्रिका, 03.09.2019)
- जल जीवन मिशन की निगरानी की जिम्मेदारी महिलाओं को (पंजाब केसरी, 05.09.2019)
- सूखती जलधाराओं को जीवित करने के लिये 'धारा विकास कार्यक्रम' (पंजाब केसरी, 09.09.2019)
- कावेरी के अतिरिक्त पानी को समुद्र में जाने से रोकने पर करें विचार : स्टालिन (राजस्थान पत्रिका, 12.09.2019)
- सरदार सरोवर नर्मदा बांध लबालब, जलस्तर 138.68 मीटर पर पहुंचा (राजस्थान पत्रिका, 16.09.2019)
- अंतर्राज्यीय जल विवाद पर नई नीति बनाने का विचार : शाह (पंजाब केसरी, 21.09.2019)
- गुजरात के 95 बांध ओवरफ्लो, 143 हाईअलर्ट (राजस्थान पत्रिका, 23.09.2019)
- मोदी ने कहा, जल संरक्षण पर 50 अरब डॉलर खर्च करेगा भारत (जनसत्ता, 24.09.2019)
- बुंदेलखंड के परमार्थ को जल संरक्षण का पहला पुरस्कार (दैनिक जागरण, 26.09.2019)
- जल प्रबंधन के लिए 21वीं शताब्दी चुनौती भरी — राजेन्द्र सिंह (राजस्थान पत्रिका, 30.09.2019)

राज्यों से समाचार

- गुवाहाटी, असम में 23.08.19 को 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर एच.ई के कार्यान्वयन के लिए असम सरकार और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए. समझौता ज्ञापन पर श्री नीरज वर्मा, प्रधान सचिव (पावर), असम सरकार और श्री बलराज जोशी, सीएमडी, एनएचपीसी ने हस्ताक्षर किए.
- उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहंद जलाशय पर फ्लोटिंग सोलर प्लेट (150 मेगावाट) स्थापित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी.

इतिहास - कोसी परियोजना

कोसी को 'बिहार का शोक' के रूप में जाना जाता है, जिसने बाढ़ और इसके जलमार्ग को पूर्व से पश्चिम में स्थानांतरित कर के पुराने समय से विनाश को जन्म दिया. कई विचार-विमर्शों में इसे हल करने के लिए व्यवहार्य समाधानों पर कोई सहमति नहीं होने के कारण, इस समस्या को केंद्रीय जल आयोग (तत्कालीन सीडब्ल्यूआईएनसी) को संदर्भित किया गया था. एक विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक जांच के बाद, 1950 में बाराखेत्र (नेपाल) में भंडारण बांध सहित एक बहुउद्देश्यीय परियोजना तैयार की गई. हालांकि, उस समय आर्थिक और वित्तीय विचारों के कारण इस पर सहमति नहीं हुई. इसके अलावा, के.ज.आ. द्वारा 1953 में भारत और नेपाल में नदियों के दोनों किनारों पर बैराज और तटबंध और सिंचाई के लिए नहर प्रणाली के निर्माण के लिए एक परियोजना पर विचार किया गया. के.ज.आ. के अधिकारियों की टीम ने 1954 में यलो और अन्य नदियों पर बाढ़ नियंत्रण कार्यों का अध्ययन करने के लिए चीन का दौरा किया. इस अध्ययन के आधार पर, कोसी पर प्रस्तावित तटबंध का फ्रीबोर्ड 4 फीट से बढ़ाकर 6 फीट किया गया और सार्वजनिक सहयोग से तटबंध बनाने का निर्णय लिया गया.

कोसी परियोजना पर भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच 25.04.1954 को समझौता हुआ. तटबंध पर काम जनवरी 1955 में शुरू हुआ और 1958 तक पूरा हो गया. चूंकि 1957 में तटबंध के प्रमुख हिस्से पूरे हो गए थे, इसलिए बाढ़ नियंत्रण का लाभ मिलना शुरू हो गया. बाद में, हनुमानसागर बैराज का निर्माण 1959 में हुआ और मार्च 1963 में पूरा हुआ. पूर्वी कोसी नहर का निर्माण 1957 में शुरू किया गया था और इसे 09.07.1964 को सिंचाई के लिए खोला गया. नहर में फाल का उपयोग 20 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किया गया और 1970 में पहली इकाई (5 मेगावाट) चालू की गई. नेपाल में छेत्रा नहर प्रणाली का निर्माण 1962 में शुरू किया गया.

1974 में बिहार सरकार द्वारा गठित कोसी बोर्ड ऑफ कंसल्टेंट ने भंडारण बांध के निर्माण के लिए के.ज.आ. के 1950 के प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया. इसके बाद 1981 में के.ज.आ. ने बराहक्षेत्र में कोसी उच्च बांध परियोजना पर व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार किया. भारत नेपाल संयुक्त परियोजना कार्यालय (जीपीओ) का गठन किया गया जिसने अगस्त 2004 में संयुक्त रूप से सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सन कोसी भंडारण सह डायवर्सन योजना के लिए जमीनी अन्वेषण और डीपीआर तैयार करने के आदेश के साथ काम करना शुरू किया.

हालाँकि, भंडारण बांधों पर प्रगति अभी तक हासिल नहीं की जा सकी है, लेकिन पहले किए गए अभियांत्रिकी हस्तक्षेप कोसी के जलमार्ग को बदलने के साथ-साथ बाढ़ के नुकसान को भी रोक सके जो स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार संभव नहीं था. परियोजना ने दोनों देशों को बाढ़ नियंत्रण में लाभ, सिंचाई और जल विद्युत प्रदान किया और यह दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है.

अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम

जल विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम: एशियाई क्षेत्र (2019) के लिए बेसिक जल विज्ञान का आयोजन 17 जून से 02 अगस्त 2019 तक सात सप्ताह की अवधि के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूसीएआर के सहयोग से किया गया. डीएल पाठ्यक्रम उन अधिकारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया जो विशेष रूप से बाढ़ पूर्वानुमान और डिजाइन बाढ़ विश्लेषण आदि के क्षेत्रों में हाइड्रोलॉजिकल डेटा के साथ काम करते हैं. इस कोर्स का उद्देश्य जलीय चक्र, अपवाह प्रक्रियाओं, इकाई हाइड्रोग्राफ, बाढ़ पूर्वानुमान, जल-विज्ञानीय मॉडलिंग के तत्व की समझ प्रदान करना और प्रतिभागियों को जल-विज्ञानीय तरीकों और पूर्वानुमान में अग्रिम अध्ययन के लिए तैयार करना है. संकाय के इस पाठ्यक्रम में एनडब्ल्यूए के मुख्य संकाय और डब्ल्यूएमओ, कॉमेट यूसीएआर से संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं. अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया.

देश	सं.
भारत	30
यूएई	02
श्रीलंका	03
पाकिस्तान	02
नेपाल	02
म्यांमार	04
मालदीव	02
मलेशिया	03
इराक	01
चीन	01
भूटान	06
कुल	56

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन , निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री प्रवीण कुमार, निदेशक(जल प्रणाली अभियांत्रिकी) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्रीमती रजिन्दर पॉल, सहायक निदेशक(राजभाषा) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in